भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1949

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात प्रसंस्करण उद्योग

1949. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा, विशेषकर और बोलंगीर और सोनपुर में इस्पात प्रसंस्करण और सहायक उद्योगों में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इन जिलों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस्पात प्रसंस्करण या निर्माण इकाइयां स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ओडिशा में इस्पात से संबंधित उद्योगों के माध्यम से कुल कितने रोजगार सृजित हुए; और

(घ) ओडिशा में डाउनस्ट्रीम इस्पात उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है और सरकार ओडिशा सहित देश के सभी राज्यों में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। उद्योग द्वारा इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में निर्णय कच्चे माल की उपलब्धता, बंदरगाह से दूरी, लॉजिस्टिक आदि सहित तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता और उत्पादन की लागत को कम करने, रोजगार बढ़ाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

जारी.....

क. सरकारी खरीद के लिए 'भारत में निर्मित' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत।

ग. केन्द्रीय बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन में वृद्धि के साथ ही अवसंरचना के विस्तार पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात की खपत में वृद्धि हुई।

घ. उत्पादन लागत कम करने के लिए कच्चे माल पर मूलभूत सीमा शुल्क का अंशांकन।

ड. घरेलू स्तर पर उत्पादित फेरो स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

******